विचार बिन्दु

मेरे दायें हाथ में कर्म है और बायें हाथ में जय! –अथर्ववेद

बिचौलियों की दखल रुके तो अन्नदाता को मिले एमएसपी का सही मायने में लाभ

केन्द्र सरकार ने रबी सीजन की गेहूं, सरसों सहित छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ सालों से बुवाई के समय ही फसलों के एमएसपी की घोषणा करना अच्छी परंपरा मानी जा सकती है। इससे किसान भी कौन सी फसल लेनी है इसका निर्णय आसानी से कर पाते हैं। एमएसपी की घोषणा करते समय यह भी दावा किया गया है कि इन सभी छहों फसलों के एमएसपी का निर्धारण लागत से अधिक किया गया है जिससे किसानों के लिए यह फसलें लाभकारी सिद्ध हो सके। दावों की माने तो लागत की तुलना में सर्वाधिक 102 प्रतिशत अधिक एमएसपी गेहूं की घोषित की गई है, सबसे कम कुसुम की लागत से 52 प्रतिशत अधिक है तो चना और जौ की लागत से 60 फीसदी अधिक घोषित की गई है। सरसों की लागत से 98 फीसदी तो मसूर की 89 प्रतिशत अधिक राशि तय की गई है। निष्कर्ष रुप से यह कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। सरकार की मानें तो लागत में खाद-बीज, कीटनाशक, सिंचाई पर व्यय के साथ ही मानव श्रम का भी समावेश किया गया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है। पर यक्ष प्रश्न यही है कि फसल आने के बाद किसान को यह मूल्य मिलेगा ही इसकी क्या गारंटी हैं? सारा झगड़ा इसी को लेकर है कि एमएसपी घोषित होती ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि किसान को उसकी फसल का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तो मिल ही जाएं। यदि इस तरह की फूलप्रुफ व्यवस्था इनविल्ट हो जाए तो किसानों को सही मायने में एमएसपी व्यवस्था का फायदा मिल सकता है। दरअसल सब कुछ होने के बाद भी किसान आज भी ठगा महसूस करता है। यही कोई डेढ़-दो माह पुरानी बात होगी जग आमनागरिकों को टमाटर दो सौ रुपए से भी अधिक में खरीदना पड़ा, आज वहीं टमाटर मण्डियों में दस रुपए के आसपास आ गया है। अब प्रश्न यह है कि टमाटर के दो सौ रुपए होने का लाभ आखिर ना तो उत्पादक किसान को मिला और ना ही आम नागरिकों को मिला। ऐसे में दोनों ही ठगे महसूस करते रह गए तो सरकार की किरकिरी हुई वह अलग।

देश में 1966-67 में सबसे पहले गेहूं की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अगस्त 1964 को एलके झा की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी घटित की थी। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था का एक विपरीत प्रभाव सामने आने पर कि किसान अन्य फसलों की जगह गेहूं की फसल पर ही केन्द्रित होने लगे तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अन्य प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरें में लाने का निर्णय किया। केन्द्र सरकार द्वारा सीएसीपी यानी कि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाने लगी। आज देश में 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसमें 7 गेहूं, धान आदि अनाज फसलें, 5 दलहनी, 7 तिलहनी, 4 नकदी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नकदी फसलों में गन्ना के सरकारी खरीद मूल्य की सिफारिश गन्ना आयोग द्वारा की जाती है तो गन्ने की खरीद भी सीधे गन्ना मिलों द्वारा की जाती है। इसी तरह से कपास की खरीद सीसीआई यानी कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा की जाती है। मुख्यतौर से अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से और दलहन व तिलहन की खरीद नेफैड द्वारा राज्यों की सहकारी संस्थाओं और अन्य खरीद केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। केरल सरकार ने 16 तरह की सब्जियों के बेस मूल्य तय कर सब्जी उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने की पहल की है तो अब हरियाणा सरकार भी केरल की तरह हरियाणा में भी सब्जियों का बेस मूल्य तय कर कर रही है।

सवाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलप्रुफ बनाना सुनिश्चित कर दे और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आंरभ हो जाएं तो निश्चित रुप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह से सैंध लगाई गई है उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक है।

2004 में एमएस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का एक फार्मूला सुझाते हुए सुझाव दिया कि उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी घोषित की जाए। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फसल के अनुसार प्रति हैक्टेयर लागत, खेती के दौरान अन्य खर्चों, भण्डारण की स्थिति, विदेशों में उपलब्धता आदि पैमाने पर आकलन कर प्रत्येक फसल की एमएसपी की सिफारिश की जाती है। 2004 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 2018-19 में उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुणा अधिक मूल्य घोषित करने का निर्णय किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा एमआईएस यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एमएसपी के दायरें में नहीं आने वाली फसलों की खरीद की व्यवस्था करती आई है। राजस्थान में लहसुन की खरीद, प्याज की खरीद आदि इसका उदाहरण है। इस साल रबी फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही न्यूनतम 52 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। रबी सीजन में सर्वाधिक असर गेहूं और सरसों पर पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए गेहू की एमएसपी में लागत की तुलना में 102 प्रतिशत और सरसों की लागत की तुलना में 98 प्रतिशत अधिक घोषित की गई है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं के 2275 रु., सरसों की 5650 रु., मसूर की 6425 रु., चना की 5440 रु., जौ की 1850 रु. और कुसुम की 5800 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

यह तो साफ है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती रही है और इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था के सुचारु संचालन और बाजार पर नियंत्रण रखना रहा है। अन्य फसलों का जहां तक सवाल है देश के अधिकांश प्रदेशों में खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई द्वारा राज्यों के मार्केटिंग फैडरेशनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा व तिलहनों और दलहनों की खरीद नैफड द्वारा भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा है। किसी समय यह सामान्य धारणा व वास्तविकता थी कि बाजार में जब भी किसी फसल के भाव एमएसपी से नीचे आने लगते तो राज्यों के मार्केटिंग फैडरेशनों द्वारा खरीद की घोषणा करने मात्र से बाजार में भावों में हल्की तेजी तो तत्काल देखने को मिल जाती थी। इसी तरह से यह वास्तविकता भी थी कि एमएसपी पर खरीद शुरु करने के समय यह माना जाता था कि कुल उत्पादन का अधिकतम 25 से 30 प्रतिशत तक खरीद होते होते बाजार में उस फसल के भाव एमएसपी के बराबर या अधिक आ जाएंगे और वास्तविकता तो यह रही कि दस से 15 प्रतिशत तक खरीद होते होते मण्डियों में भाव लगभग एमएसपी के आसपास आ ही जाते थे। पर करीब एक दशक से स्थितियों में तेजी से बदलाव आया है। माने या ना माने पर यह काफी हद तक सही है कि एमएसपी खरीद व्यवस्था में अब निजी खरीददारों की भागीदारी बढ़ गई है। इस आरोप को सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि छोटे किसानों से उनकी फसलों को कम दामों में खरीद कर उनके नाम से एमएसपी पर खरीद केन्द्रों पर बेच कर किसान के नाम पर उसका लाभ बिचौलिएं लेने लगे है। यही कारण है कि इस तरह के उदाहरण आम है कि कई स्थानों पर उस क्षेत्र में कुल पैदावार से भी अधिक की खरीद एमएसपी पर देखने को मिल जाती है।

दरअसल बिचौलियों ने एमएसपी खरीद व्यवस्था में सैंध लगा दी है। किसान से ही खरीद और ऑनलाईन व्यवस्था के बावजूद इस व्यवस्था का लाभ बिचौलिएं अधिक उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलप्रुफ बनाना सुनिश्चित कर दे और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आंरभ हो जाएं तो निश्चित रुप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह से सैंध लगाई गई है उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजार व्यवस्था का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि जब तक किसान की पूरी फसल बाहर नहीं आ जाती तब तक क्या कारण है कि बाजार में उस फसल के भाव एमएसपी के बराबर नहीं आते। इसका पर्दे के पीछे का खेल यही लगता है कि बिचौलियों ने इसका तोड़ निकाल लिया है और वह यह कि किसान से उसकी फसल और डिटेल ले लेते हैं और फिर किसान के नाम से लाभ यह ताकतें ले जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्षेत्र में उत्पादित फसल से अधिक खरीद के आंकड़े मिलना आम होता जा रहा है। ऐसे हालात में सरकार का और अधिक दायित्व हो जाता है ताकि व्यवस्था को प्रभावित करती बाजार ताकतों को भी व्यवस्था से हटाने का दायित्व सरकारों का हो जाता है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राजस्थान : उत्कृष्ट उच्च शिक्षा का उद्देश्य

अशोक कुमार

राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए काम कर रही है। परंतु वर्तमान में राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा मिश्रित है। एक तरफ, राज्य में उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं हैं। राजस्थान में 26 राज्य सार्वजनिक विश्व विद्यालय, सर्वाधिक 52 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। इसके विपरीत आन्ध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, और तेलंगण में कोई भी निजी विश्वविद्यालय नहीं है। 7 डीम्ड विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी) और एक केंद्रीय और राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 30 है , जिनमें 5075 एमबीबीएस सीटें हैं। ये विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर की डिठाी प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में, राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के बावजूद, राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होने चाहिए:-राज्य में उच्च शिक्षा में नामांकन दर 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सूचकांक को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना राज्य में उच्च शिक्षा के लिए रोजगार दर 75 प्रतिशत तक बढ़ाना, राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं हैं। राज्य के अधिकांश कॉलेजों में बुनियादी ढांचा और संसाधनों की कमी है। इसके अलावा, शिक्षकों की गुणवत्ता भी एक चिंता का विषय है। कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, और जो शिक्षक मौजूद हैं, उनकी योग्यता भी संदिग्ध है। हाल के वर्षों में, राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचा और संसाधनों में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, सरकार ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए अधिक संसाधनों में निवेश करना चाहिए। इससे बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार होगा, और शिक्षकों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। राज्य को शिक्षकों की योग्यता में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण और पेशेवर विकास शामिल होना चाहिए। राज्य को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

इस प्रणाली से राज्य को उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। राज्य को सभी वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए, राज्य को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। राज्य को उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए, राज्य को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने से राजस्थान एक शिक्षित और कुशल जनशक्ति विकसित करने में सक्षम होगा, जो राज्य के आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान देगा।इससे राज्य के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे

यहाँ कुछ विशिष्ट उपाय दिए गए हैं जो राजस्थान मिशन 2030 के तहत उच्च शिक्षा की दशा में सुधार के लिए किए जा सकते हैं:- राज्य को कक्षा 12 के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश दर में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। राज्य को उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। राज्य को उच्च शिक्षा में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। राज्य को उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इन उपायों से राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा के लिए कुछ नए विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इन विषयों को राजस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए।

यहाँ कुछ संभावित नए विषय दिए गए हैं: -राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से राजस्थान को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और एक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और राजस्थान को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी होने के लिए अपनी जनशक्ति को डिजिटल कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। वहीं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य को उच्च शिक्षा में क्रिएटिव आर्ट्स, डिजाइन और मीडिया जैसे विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, राज्य को उच्च शिक्षा में मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इन विषयों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषय शामिल होने चाहिए। इन विषयों से छात्रों को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने में मदद मिलेगी। इन विषयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषय शामिल होने चाहिए। इन विषयों से छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। इन विषयों में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषय शामिल होने चाहिए। इन विषयों से छात्रों को समाज की समझ विकसित करने और अपने समुदायों में योगदान करने में मदद मिलेगी। इन विषयों को शामिल करने से राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा में सुधार होगा और राज्य को एक अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकसित करने में मदद मिलेगी।

भविष्य मे राजस्थान में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी चाहिए:-छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षकों की योग्यता में सुधार करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उच्च शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसके लिए, राज्य को छात्रवृत्ति, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। छात्रों को आधुनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए निवेश करने चाहिए। छात्रों को छात्र जीवन के अवसरों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छात्र गतिविधियों और क्लबों को बढ़ावा देना चाहिए।

यहाँ कुछ विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं जो राजस्थान मिशन 2030 के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए प्रदान की जा सकती हैं:- राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए। राज्य को छात्रों को ऋण प्रदान करना चाहिए ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य को छात्रों के लिए आवास प्रदान करना चाहिए। राज्य को छात्रों के लिए भोजन प्रदान करना चाहिए। राज्य को छात्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी चाहिए। राज्य को छात्रों के लिए खेल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। राजस्थान में उच्च शिक्षा के साथ साथ छात्रों के लिए कोचिंग केंद्रभी खोले जाने चाहिए। यह छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद करेगा और उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने में मदद करेगा। वे छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके प्रदान कर सकते हैं। वे छात्रों को अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने से राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा में सुधार होगा और राज्य एक शिक्षित और कुशल जनशक्ति विकसित प्रदेश होगा।

अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर विश्व विद्यालय,गोरखपुर विश्वविद्यालय

सर्दी के साथ पर्यटन सीजन का आगाज़, देशी सैलानी जैसलमेर आने लगे

- **इजराइल-हमास युद्ध से विदेशी सैलानियों की आवक पर असर पड़ा, देशी पर्यटकों का लगने लगा मेला**
- **पर्यटकों की आवक शुरु होने से जैसलमेर में पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं**

जैसलमेर, (निसं)। कोरोना के बाद अब इजराइल और हमास युद्ध से विदेशी सैलानियों की आवक पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इजराइल और हमास के युद्ध का असर जैसलमेर पर्यटन सीजन पर पड़ सकता है। इजराइल से भारत की फ्लाइटें बंद कर दी गई है। वहीं इजराइल के लोग अपने देश को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं। भारत में बैठे इजराइल के लोग भी युद्ध के बीच अपने वतन जाने के लिए तैयार बैठे है। ऐसे में इजराइल से आने वाले पर्यटक इस युद्ध के कारण जैसलमेर नहीं आ पाएंगे। वहीं अन्य देशों के लोग भी इजराइल-हमास के युद्ध की परिस्थितियों के बीच अपने वतन को छोड़ना कम ही चाहेंगे। इस वजह से इस बार विदेशी पर्यटकों की आवक कम रहने की संभावना है।

बारिश के बाद सर्दी चमकने के साथ ही पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली व हरियाणा सहित कई राज्यों से देशी सैलानी जैसलमेर भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। पर्यटकों की आवक के साथ ही होटल व रिसोर्ट्स में रौनक बढ़ चुकी है। जैसलमेर में सर्दी की शुरुआत होते ही पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। पूरी सर्दी जैसलमेर में सैलानियों की बूम रहती है और गर्मी की दस्तक के साथ ही ऑफ सीजन शुरु हो जाती है। आमतौर पर सितंबर में ही सैलानियों की आवक शुरु हो जाती है। लेकिन इस बार गर्मी का असर लंबा होने के कारण पर्यटकों की आवक नहीं हुई। इस बार नवरात्र के साथ ही सर्दी का असर शुरू हो गया और पर्यटकों की आवक भी शुरु हो गई। जिससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए है।

वर्तमान में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब के पर्यटक घूमने के लिए आ रहे है। दीपावली पर स्वर्णनगरी में गुजराती सैलानियों का मानसून आएगा। दीपावली की सीजन में गुजराती सैलानी अधिक पहुंचते है। धनतेरस पर गुजराती अपने घरों पर लक्ष्मी पूजन कर वहां से रवाना हो जाते हैं। दीपावली की पूरी छुट्टियों का आनंद आमतौर पर गुजराती जैसलमेर में उठाते है।

दीपावली पर लाखों गुजराती सैलानी स्वर्णनगरी भ्रमण पर आते हैं। गुजराती सैलानियों के आने से भी पर्यटन को पंख लगेंगे। पर्यटकों की आवक शुरु होते ही जैसलमेर शहर में पर्यटकों की रौनक है। सुबह से लेकर रात तक पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। शहर के सोनार दुर्ग, गड़ीसर तालाब, पटवा हवेली आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। स्थानीय व्यवसायियों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है। इस बार जैसलमेर में भारी तादाद में पर्यटकों के आने की संभावना है।

जैसलमेर शहर के सोनार दुर्ग, गड़ीसर तालाब, पटवा हवेली आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है।

डॉ. कृति भारती को यूथ लीडरशिप अवॉर्ड

- **बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की साहसिक मुहिम और बाल व महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए सम्मानित किया**

जोधपुर, (कासं)। ख्वाब फाउंडेशन के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम को समर्पित अन्तरराष्ट्रीय युवा महोत्सव में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ.कृति भारती को कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया।

डॉ. कृति भारती को बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की साहसिक मुहिम और बाल व महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान से एकमात्र वर्ल्ड टॉप टेन चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट व एडवोकेट डॉ. कृति भारती को यूथ लीडरशिप अवॉर्ड दिया गया।

अन्तरराष्ट्रीय महोत्सव में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, राजीव गांधी सेंट्रल युनिवर्सिटी इटानगर अरूणाचल प्रदेश के कुलपति साकेत कुशवाहा, ख्वाब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. मुन्ना कुमार, डॉ. अर्चना भट्टाचार्य, गांधीवादी विचारक शुभ्रतो रॉय, बॉलीवुड अभिनेता हीरो राजन व अन्य मौजूद रहे। महोत्सव में सउदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश सहित 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं भारत के 28 राज्यों के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने शिरकत की। ख्वाब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. मुन्ना कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष यह अवार्ड विश्व स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों को दिया जाता है।

शाहपुरा के नन्हे तैराकों ने पदक जीते

- **मध्यप्रदेश में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन तैराकी प्रतियोगिता में पदक जीते**

भीलवाड़ा, (निसं)। भोपाल मध्यप्रदेश में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन तैराकी प्रतियोगिता में शाहपुरा के नन्हे तैराकों ने पदकों की झड़ी लगाते हुए शाहपुरा जिले का नाम रोशन किया।

कोच योगेश बघेरवाल ने बताया कि 15 से 19 अक्टूबर तक आयोजित हुई प्रतियोगिता में शाहपुरा के एक स्कूल के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें मिस्टी शर्मा ने 200 मी. इंडिविजुअल मेडले में स्वर्ण पदक 100 मी फ्रीस्टाइल में रजत पदक 200 मी. फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक आदित्य उपाध्याय ने 100 मी. बटरफ्लाई में कांस्य पदक 200 मी. इंडिविजुअल मेडले में कांस्य पदक लोकेंद्र सिंह खंगारोत ने 100 मी. बैक स्ट्रोक में रजत पदक 50 मी. बैक स्टॉक में कांस्य पदक अंशिका ने 100 मी. बैक स्ट्रोक में रजत पदक 100 मी फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक 200 मी. फ्री स्टाइल में कांस्य पदक 50 मी. बैक स्ट्रोक में कांस्य पदक आराध्या ने 50 मी. ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत पदक प्राप्त कर शाहपुरा का नाम रोशन किया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 21 अक्टूबर, 2023

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2080, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सांय 7:54 तक, सुकर्मा योग रात्रि 12:36 तक, गर करण दिन 10:39 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में रात्रि 1:38 से संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-धनु, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग रात्रि 7:54 से रात्रि 9:54 तक रहेगा। भद्रा रात्रि 9:34 से रविवार प्रातः 8:57 तक रहेगी। आज महा सप्तमी, सरस्वती पूजन है। त्रेदिनात्मक दुर्गा पूजन आरम्भ होगा। अन्नपूर्ण परिक्रमा रात्रि 9:54 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:58 से 9:22 तक, चर 12:11 से 1:36 तक, लाभ-अमृत 1:36 से 4:25 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:33, सूर्यास्त 5:50

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

वृष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

कन्या
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर
अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।